रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3714] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 18, 2019/कार्तिक 27, 1941
No. 3714] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 18, 2019/KARTIKA 27, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2019

का.आ. 4137(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता का संरक्षण करने तथा उसमें सुधार करने और तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने, कम करने तथा नियंत्रित करने के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बने राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, अर्थात् :-

1.	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	अध्यक्ष,पदेन
2.	तटीय विनियमन जोन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित विशेष सचिव या अपर सचिव	सदस्य,पदेन
3.	सदस्य सचिव, केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण	सदस्य, पदेन
4.	संयुक्त सचिव (पर्यटन) या निदेशक (पर्यटन), पर्यटन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
5.	उप-महानिदेशक (मत्स्य), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	सदस्य, पदेन
6.	निदेशक, राष्ट्रीय पोषणीय तटीय प्रबंध केन्द्र, चेन्नई	सदस्य, पदेन

7.	डा. शैलेश नाइक, सचिव (सेवानिवृत्त), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य, पदेन
8.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), आन्ध्र प्रदेश सरकार	सदस्य, पदेन
9.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), तमिलनाडु सरकार	सदस्य, पदेन
10.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), गुजरात सरकार	सदस्य, पदेन
11.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), गोवा सरकार	सदस्य, पदेन
12.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), कर्नाटक सरकार	सदस्य, पदेन
13.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), केरल सरकार	सदस्य, पदेन
14.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), महाराष्ट्र सरकार	सदस्य, पदेन
15.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), ओडिसा सरकार	सदस्य, पदेन
16.	प्रधान सचिव (पर्यावरण), पश्चिमी बंगाल सरकार	सदस्य, पदेन
17.	तटीय संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित संयुक्त सचिव (संघ राज्यक्षेत्र), गृह मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
18.	संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
19.	संयुक्त सचिव-सलाहकार-वैज्ञानिक जी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
20.	संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
21.	तटीय विनियमन जोन से संबंधित संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य सचिव, पदेन;

2. अपना मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति दस सदस्यों से होगी और यदि वैठक में गणपूर्ति नहीं होती है तो तीस मिनट के लिए बैठक स्थगित कर दी जाएगी और पुनः बैठक की जाएगी।

4. प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा, अर्थात्:-

(i) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हो, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकारियों और संघ राज्य क्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों की कार्रवाईयों का समन्वय करेगा ।

(ii) प्राधिकरण, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकारियों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकारियों से प्राप्त तटीय जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के प्रस्तावों का परीक्षण करेगा और उसके लिए केन्द्रीय सरकार को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करेगा ।

(iii) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हो, के उपबंधों के उल्लंघनों के मामलों का स्वःप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुनर्विलोकन करेगा और जहाँ यदि आवश्यक हो, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करेगा।

(iv) प्राधिकरण, संबंधित राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र सरकारों या प्रशासनों को तटीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार से संबंदित विषयों में तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा और तटीय क्षेत्र प्रबंध से संबंधित विषयों में नीति, नियोजन, अनुसंधान और विकास, उत्कर्ष केंद्रो की स्थापना तथा वित्तपोषण पर केन्द्रीय सरकार को सलाह दे सकेगा।

IndiaCode

(v) प्राधिकरण, राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकारियों और संघ राज्यक्षेत्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत किए गए तटीय जोन प्रबंध योजनाओँ (सीजेडएमपीएस), तटीय द्वीप विनियमन जोन योजना (आईसीआरजेडपी), क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओँ, एकीकृत द्वीप प्रबंध योजनाओँ (आईआईएसपीएस) और उनमें उपांतरणोँ की परीक्षा करेगा और उसका अनुमोदन करेगा।

(vi) प्राधिकरण, अपनी बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त से संबंधित सूचना को इंटरनेट वेबसाइट www.envfor.nic.in के माध्यम के साथ ही लोकाधिकारी क्षेत्र में प्रदर्शन करेगा।

(vii) प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियाँ और कृत्य, केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

(viii) प्राधिकरण, जहाँ कहीँ अपेक्षित हो, अपनी बैठक के दौरान किसी अन्य विशेषज्ञ को सदस्य के रुप में आमंत्रित करेगा।

(ix) पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए विनिश्च्य के मानदंडों के अनुसार भत्ते संदत्त किए जाँएगें।

[फा. सं. जे-17011/18/1996-आईए- III (पीटी)]

अरविंद कुमार नौटियाल, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2019

S.O. 4137(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby for the purpose of protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal areas, hereby constitutes the National Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons for a period of two years with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette, namely:-

(1)	Secretary, Ministry of Environment Forest and Climate Change	Chairman, *exofficio*
(2)	Special Secretary or Additional Secretary dealing with Coastal Regulation Zone, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Member, *exofficio*
(3)	Member Secretary, Central Ground Water Authority	Member, *exofficio*
(4)	Joint Secretary (Tourism) or Director (Tourism), Ministry of Tourism	Member, *exofficio*
(5)	Deputy Director General (Fisheries), ICAR, M/o Agriculture and Farmers Welfare	Member, *exofficio*
(6)	Director, National Centre for Sustainable Coastal Management, Chennai	Member, *exofficio*
(7)	Dr. Shailesh Naik, Secretary (Retd.), Ministry of Earth Sciences, New Delhi	Member, *exofficio*
(8)	Principal Secretary(Environment), Government of Andhra Pradesh	Member, *exofficio*
(9)	Principal Secretary(Environment), Government of Tamil Nadu	Member, *exofficio*
(10)	Principal Secretary(Environment), Government of Gujarat	Member, *exofficio*
(11)	Principal Secretary(Environment), Government of Goa	Member, *exofficio*
(12)	Principal Secretary(Environment), Government of Karnataka	Member, *exofficio*
(13)	Principal Secretary(Environment), Government of Kerala	Member, *exofficio*
(14)	Principal Secretary(Environment), Government of Maharashtra	Member, *exofficio*
(15)	Principal Secretary(Environment), Government of Odisha	Member, *exofficio*
(16)	Principal Secretary(Environment), Government of West Bengal	Member, *exofficio*
(17)	Joint Secretary(UT), Ministry of Home Affairs, Government of India,	Member, *exofficio*

	dealing with Coastal Union Territories	
(18)	Joint Secretary, Ministry of Urban Development, Government of India	Member, *exofficio*
(19)	Joint Secretary/Adviser/Scientist G, Ministry of Earth Sciences, Government of India	Member, *exofficio*
(20)	Joint Secretary, Ministry of Defence, Government of India	Member, *exofficio*
(21)	Joint Secretary dealing with CRZ, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Member Secretary, *exofficio.*

2. The Authority shall have its headquarter at New Delhi.

3. The quorum of the meeting of the authority shall be 10 members and in case the quorum is not available the meeting shall be adjourned for 30 minutes and shall be reconvened.

4. The Authority shall exercise the following powers and function, namely:-

(i) The authority shall co-ordinate the actions of the State Coastal Zone Management Authorities and the Union Territory Coastal Zone Management Authorities under the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act.

(ii) The Authority shall examine the proposals for changes or modification in the clarification of Coastal Zone Areas and in the Coastal Zone Management Plans received from the State Coastal Zone Management Authorities and the Union Territory Coastal Zone Management Authorities, and make specific recommendations to the Central Government therefor.

(iii) The Authority shall hold review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or any other law which is relatable to the objects of the said Act, either *suo-motu*, or on the basis of complaint made by an individual or body, or organization, and wherever necessary, issue directions under Section 5 of the said Act.

(iv) The Authority shall provide technical assistance and guidance to the concerned State Government, Union Territory Governments or Administrations, in the matters relating to protection and improvement of the coastal environment and may advise the Central Government on policy, planning, research and development, setting up of centers of excellence and funding in matters relating to coastal areas management.

(v) The Authority shall examine and approve the Coastal Zone Management Plans (CZMPs), Island Coastal Regulation Zone Plan (ICRZP), Integrated Island Management Plans (IIMPs) and modifications thereof submitted by the State Coastal Zone Management Authorities and Union Territory Coastal Zone Management Authorities.

(vi) The Authority shall place information regarding the agenda and minutes of its meetings in the public domain, including through internet website www.envfor.nic.in .

(vii) The foregoing powers and functions of the Authorities shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

(viii) The Authority may, whenever required, may invite other expert as a member during its meeting.

(ix) A member, other than an *exofficio* Member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.

[F.No.J-17011/18/1996-IA.III(Pt)]

ARVIND KUMAR NAUTIYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.19 19:19:20 +05'30'